माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी के समक्ष,

कांता देवी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

राम कुमार और अन्य-प्रतिवादी

2019 का एफएओ नंबर 1260

17 सितंबर 2020

मोटर वाहन अधिनियम, 1988—धारा 140, 166—मौत का मामला—मृतक, 53 वर्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में खलासी के रूप में कार्यरत था—दुर्घटना हरियाणा के समालखा में हुई—ट्रिब्यूनल ने ड्राइवर को लापरवाह माना और बीमा को दावेदारों, विधवा और को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। बेटा- मुआवज़ा राशि का आकलन 11 के गुणक को लागू करके, भविष्य की संभावनाओं के लिए 15% आय जोड़कर और पारंपरिक मदों के तहत देय राशि देकर किया गया था- हालांकि, 7 के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए 26,67,168/- रुपये की राशि काट ली गई थी। हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 के तहत वर्षों - इस याचिका पर अपील दायर की गई कि मृतक हरियाणा सरकार का कर्मचारी नहीं था, और दावेदार को वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं थी - क्योंकि मृतक कार्यरत था। डीडीए, जिसने वित्तीय सहायता के लिए 2006 के हरियाणा नियमों के समान कोई नियम नहीं बनाया था, अनुकंपा वित्तीय सहायता की कटौती के संबंध में ट्रिब्यूनल की टिप्पणी गलत थी - ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी को गलत कटौती के आधार को समझाने के लिए बुलाया गया था - आगे कहा गया, हमारे कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की त्रुटि को स्वीकार करती है और इसके मद्देनजर अपील और संशोधन प्रदान करती है - एक न्यायाधीश जिसने कोई त्रुटि नहीं की है उसका जन्म होना अभी बाकी है - किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ वास्तविक त्रुटि के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि स्पष्ट आरोप न हों कदाचार, बाहरी प्रभाव, किसी भी प्रकार की संतुष्टि आदि - अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल पारित गलत आदेश के आधार पर शुरू नहीं की जानी चाहिए - तथ्यों पर, निष्कर्षों को दिखाने के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत या अन्य सामग्री एनिमेटेड नहीं थी दुर्भावनापूर्ण या असंगत विचारों से अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता होती है - चूंकि न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित गलत आदेशों के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हो

सकती है, इसलिए यह उचित होगा कि अधिकारियों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जाए - चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी को ऐसे गलत आदेशों से जुड़े मामलों को समय-समय पर संकलित करने और अधिकारियों के लिए आयोजित इंडक्शन/रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान हुई त्रुटियों को इंगित करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, वर्तमान मामले में, मृतक बलवान सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में खलासी के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ने हरियाणा 2006 नियमों के समान कोई नियम नहीं बनाया है, जो मृत कर्मचारी के अंतिम वेतन और भत्ते के बराबर राशि के भुगतान द्वारा अपने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे किसी भी नियम के अभाव में अपीलकर्ता/दावेदार मृतक द्वारा अंतिम बार लिए गए सात साल या किसी अन्य अवधि के वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि के भुगतान द्वारा किसी भी अनुकंपा वित्तीय सहायता के हकदार नहीं थे। पीडब्लू-3 चंदर भान, बैलदार, एक्सईएन कार्यालय, दिल्ली ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि दावेदार नंबर 1-मृतक-बलवान सिंह की विधवा को विभाग से पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रति माह 13,660/- रुपये की राशि मिल रही थी। अपीलकर्ता/दावेदार नंबर 1 मृत कर्मचारी बलवान सिंह की विधवा को पेंशन का भुगतान भी विरोधाभासी है और इस प्रकार अपीलकर्ताओं/दावेदारों की भुगतान की पात्रता के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा अपीलकर्ताओं/दावेदारों को ऐसी किसी भी अनुकंपा वित्तीय सहायता के वास्तविक भुगतान दोनों को अस्वीकृत करता है। मुआवजे की राशि में से अनुकंपा वित्तीय सहायता की राशि की कटौती के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं थीं। ट्रिब्यूनल द्वारा अपने निर्णय/निर्णय के पैरा संख्या 24 और 25 में की गई टिप्पणियाँ गलत थीं। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों को देय 35,56,069/- रुपये की मुआवजा राशि में से 26,67,168/- रुपये की राशि गलत तरीके से काट ली और विवादित पुरस्कार भौतिक अवैधता से ग्रस्त है और इसमें संशोधन के योग्य है। संबद्ध।

(पैरा 22)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्पष्ट रूप से, विवादित पुरस्कार के पैरा संख्या 24 और 25 में टिप्पणियाँ ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्यों की गलत धारणा पर की गई थीं कि मृतक, जो हरियाणा का निवासी था, हरियाणा सरकार का कर्मचारी था। हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की ग़लती को स्वीकार करती है और इसके मद्देनजर अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। (**के.पी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें: 1994 सप्लिमेंट (1) एससीसी 540**)। गलती करना मानवीय

है और कोई भी अचूक नहीं है। ऐसा न्यायाधीश अभी तक पैदा नहीं हुआ है जिसने कोई गलती न की हो। (**अमर पाल सिंह बनाम यूपी राज्य (एससी) देखें: 2012 (3) आर.सी.आर. (सिविल) 963** और **"के" एक न्यायिक अधिकारी के मामले में (2001) 3 एससीसी 54**)। वास्तविक त्रुटि के लिए किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कदाचार, बाहरी प्रभाव, किसी भी प्रकार की संतुष्टि आदि के स्पष्ट आरोप न हों, अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इस आधार पर शुरू नहीं की जानी चाहिए कि न्यायिक अधिकारी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। (देखें **काशी नाथ रॉय बनाम बिहार राज्य, 1996(2) आरसीआर (आपराधिक) 340** और **कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य: 2019 (10) एससीसी 640**)। उच्च न्यायालयों की भूमिका अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह होती है और वरिष्ठ न्यायालयों का दृष्टिकोण सुधारात्मक होना चाहिए। (एक न्यायिक अधिकारी **"के" के मामले में देखें (2001) 3 एससीसी 54**)। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कोई शिकायत या कोई अन्य सामग्री नहीं है कि निष्कर्ष किसी दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों से प्रेरित थे ताकि प्रशासनिक पक्ष पर ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता हो।

(पैरा 23)

आगे कहा गया है कि हालांकि, इस अपील से अलग होने से पहले यह देखा जा सकता है कि कभी-कभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा तथ्य या कानून में त्रुटियों वाले गलत आदेश पारित किए जाते हैं। अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए इसके खिलाफ अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं करने की स्थिति में ऐसे आदेशों के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर हानि हो सकती है। यह उचित होगा कि न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने और अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा बार-बार की जाने वाली त्रुटियों से बचने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जाए। चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ को समय-समय पर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार विजिलेंस या रजिस्ट्रार न्यायिक और संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीशों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करके न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित ऐसे गलत आदेशों से जुड़े मामलों को संकलित करने और न्यायिक अधिकारियों को की गई त्रुटियों को इंगित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने उनके लिए आयोजित इंडक्शन/रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान संबंधित न्यायिक अधिकारियों और इसमें शामिल मामलों के विवरण का खुलासा न करने के समर्पित प्रयास किए, हालांकि निर्णयों की रिपोर्टिंग के मद्देनजर इसके बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। इस न्यायालय के आदेशों को इस न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड करना।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशित मलिक।

प्रतिवादी क्रमांक 1 की उपस्थिति अनावश्यक मानी गई।

प्रतिवादी नंबर 2-बीमा कंपनी के लिए पॉल एस. सैनी, वकील।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी,

(1) दावेदारों-कांता देवी (विधवा) और मृतक-बलवान सिंह के गौरव कुमार (पुत्र) ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पानीपत (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हुए वर्तमान अपील दायर की है। दिनांक **31.10.2018 को 2017 के एमएसीटी केस नंबर आरबीटी - 82 में 'कांता देवी और अन्य बनाम'** शीर्षक से पारित किया गया। समालखा क्षेत्र में 05.03.2017 को हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने के कारण बलवान सिंह की मृत्यु के कारण राणा कुमार और एक अन्य।

(2) दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एम.वी. अधिनियम') की धारा 140 के साथ पठित धारा 166 के तहत मुआवजा देने के लिए उपरोक्त दावा याचिका इस आधार पर दायर की कि 05.03.2017 को मृतक-बलवान सिंह और उनके ससुर महाबीर सिंह मोटरसाइकिल पर दिल्ली से ग्राम गढ़ी सिकंदरपुर, थाना मॉडल टाउन, पानीपत आ रहे थे। लगभग 4:00 बजे जब वे जीटी रोड पर पेट्रोल पंप, समालखा के पास पहुंचे अचानक एक पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR-67A-8312 है, जिसे उसके मालिक प्रतिवादी नंबर 1 बहुत तेज गति से तेजी और लापरवाही से चला रहा था, पीछे से आई और उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण मृतक बलवान सिंह गिर गया। सड़क पर जबकि महावीर सिंह सड़क के कच्चा किनारे पर गिर गए और उन्हें कई चोटें आईं। बलवान सिंह को पार्क अस्पताल, जी.टी. ले जाया गया। रोड, पानीपत जहां उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एफआईआर नंबर 157 दिनांक 07.03.2017 को पुलिस स्टेशन समालखा, जिला पानीपत में भारतीय दंड संहिता, 1980 की धारा 279 और 304-ए के तहत दर्ज किया गया था। मृतक की उम्र लगभग 53 वर्ष थी और वह दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में खलासी के रूप में काम करके प्रति माह 35,000 रुपये कमाता था।तदनुसार, दावेदारों ने प्रतिवादी नंबर 1-मालिक/ड्राइवर और प्रतिवादी नंबर 2-बीमाकर्ता के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग 24% प्रति वर्ष की दर से लागत और ब्याज के साथ 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की प्रार्थना की।

(3) नोटिस पर, दावा याचिका का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया। अपने लिखित बयान में प्रतिवादी नंबर 1 ने सही और भौतिक तथ्यों को दबाने, आवश्यक पक्षों के गैर-जुड़ने वाले और गलत-जोड़ने वाले, लोकस स्टैंडी की कमी आदि के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां लीं, दुर्घटना से इनकार किया और प्रतिवादी नंबर 2 के दायित्व का दावा किया- दावा याचिका स्वीकृत होने की स्थिति में बीमाकर्ता। अपने लिखित बयान में प्रतिवादी नंबर 2 ने गैर-रखरखाव, मिलीभगत, प्रतिवादी नंबर 1-मालिक/चालक के पास दुर्घटना के समय कोई वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और बीमा के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां लीं। प्रतिवादी नंबर 1-मालिक/चालक द्वारा नीति और मोटर साइकिल के मृतक/चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। प्रतिवादी नंबर 2 ने भी याचिका में दिए गए महत्वपूर्ण कथनों का खंडन किया और अपने दायित्व से इनकार किया।

(4) ट्रिब्यूनल ने मुद्दों को तैयार किया और पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को दर्ज किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि बलवान सिंह की मृत्यु पंजीकरण संख्या एचआर-67ए-8312 वाली पिक अप की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जिसके पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को बलवान सिंह की मौत के लिए मुआवजे के भुगतान का हकदार माना। ट्रिब्यूनल ने मृतक की आयु 53 वर्ष मानी, उसकी मासिक आय 35,139/- रुपये आंकी, भविष्य की संभावनाओं के लिए आय का 15% जोड़ा, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती की, 11 का गुणक लागू किया और उसमें से बाहर कर दिया। सात वर्षों के लिए मृतक के अंतिम आहरित वेतन और भत्तों की दर से वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु 26,67,168/- रुपये की कटौती की गई राशि 35,56,069/- रुपये की गणना की गई। 8,88,901/- रुपये की शेष राशि में ट्रिब्यूनल ने कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 40,000/- रुपये, परिवहन और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/- रुपये की राशि जोड़ी। और याचिका दायर करने की तारीख से उत्तरदाताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने तक 7.5% की दर से लागत और ब्याज के साथ कुल 9,58,901 रुपये का मुआवजा दिया गया।

(5) व्यथित महसूस करते हुए, दावेदारों ने 26,67,168/- रुपये की राशि की कटौती को चुनौती देते हुए और दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग करते हुए वर्तमान अपील दायर की है।

(6) पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद 31.07.2020 को अपील की अनुमति दी गई थी, लेकिन फैसले पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले यह पता चला कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख

नहीं किया गया था, जिस पर हस्ताक्षर करने से पहले आदेश को वापस ले लिया गया था। निर्णय दिया गया और मामले को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया।

(7) मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(8) शुरुआत में ही यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों के अनुसार बलवान सिंह की मृत्यु पंजीकरण संख्या एचआर-67ए वाली पिकअप की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी- 8312 प्रतिवादी नंबर 1 के मालिक/चालक द्वारा, प्रतिवादी नंबर 1 के मालिक/चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है, दावेदार मृतक के आश्रित और कानूनी प्रतिनिधि हैं, और दावेदारों के अधिकार और उत्तरदाताओं नंबर 1 के संयुक्त और कई दायित्व हैं। और बलवान सिंह की मृत्यु के लिए मुआवजे के भुगतान को उत्तरदाताओं द्वारा कोई अपील या प्रति-आपत्ति दायर करके चुनौती नहीं दी गई है। अन्यथा भी, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित सराहना के आधार पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।]

(9) अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील ने दो गुना दलीलें दी हैं। सबसे पहले अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक बलवान सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में खलासी के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (संक्षेप में 'हरियाणा 2006 नियम') के समान कोई नियम नहीं बनाया है, जो अपने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वेतन भुगतान के माध्यम से अनुकंपा सहायता प्रदान करता है। और मृत कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित दर पर भत्ते। अपीलकर्ता/दावेदार नंबर 1 को विभाग से पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रति माह 13,660/- रुपये की राशि मिल रही है, जैसा कि पीडब्लू-3 चंदर भान, बेलदार, एक्सईएन कार्यालय, दिल्ली ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। मृतक बलवान सिंह के आश्रितों को अगले सात वर्षों के लिए वेतन भुगतान के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा अपने फैसले के पैरा नंबर 24 में की गई टिप्पणियाँ गलत हैं और अपीलकर्ताओं/दावेदारों को देय मुआवजा राशि का ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से 26,67,168/- रुपये की कटौती की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशि शर्मा और अन्य***[1] मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं थीं। अपीलकर्ता अपीलकर्ताओं/दावेदारों को देय मुआवजा राशि में से रु. 26,67,168/- की कटौती के बिना मुआवजा राशि के भुगतान के हकदार हैं। अपीलकर्ताओं/दावेदारों के लिए विद्वान वकील ने अगले स्थान पर तर्क दिया है कि मृतक की

[1] IV (2016) एसीसी 340; 2016(4) आरसीआर (सिविल) 569

आजीविका और उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 11 से अधिक गुणक को ट्रिब्यूनल द्वारा लागू किया जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार और संपत्ति के नुकसान के लिए बहुत कम मुआवजा दिया है और प्यार और स्नेह और पारिवारिक कंसोर्टियम के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया है। अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील ने तदनुसार प्रार्थना की है कि विवादित पुरस्कार को संशोधित किया जा सकता है और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाया जा सकता है।

(10) दूसरी ओर, जहां तक अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील के तर्कों के पहले चरण का संबंध है, प्रतिवादी नंबर 2-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं किया है और काफी हद तक स्वीकार किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हरियाणा 2006 नियमों के समान कोई नियम नहीं था; अपीलकर्ताओं/दावेदारों को कोई समान अनुकंपा सहायता नहीं मिली; अपीलकर्ता/दावेदार नंबर 1 को केवल पेंशन मिल रही थी और शशि शर्मा के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियाँ लागू नहीं थीं और उन्होंने इस संबंध में पुरस्कार के संशोधन पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील की दलीलों के दूसरे चरण का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि ट्रिब्यूनल ने सही गुणक लागू किया और कंसोर्टियम के नुकसान के प्रमुखों के तहत उचित राशि प्रदान की। संस्कार और संपत्ति की हानि जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रतिवादी नंबर 2 बीमा कंपनी के वकील ने आगे तर्क दिया है कि ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय के आकलन में मृतक के वेतन से की जाने वाली कटौतियों को गलत तरीके से शामिल किया है और आयकर के लिए कोई कटौती नहीं की है और दी गई राशि हो सकती है उचित रूप से कम किया जा सकता है और पुरस्कार को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है।

(11) वर्तमान मामले में मृतक-बलवान सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में खलासी के रूप में कार्यरत था और पीडब्लू-3 चंदर भान, बैलदार, एक्सईएन कार्यालय, दिल्ली द्वारा गवाही के अनुसार मृतक-बलवान सिंह को 35,139/- रुपये का वेतन मिल रहा था। उनकी मृत्यु के समय पीडब्लू-3 चंदर भान की गवाही वेतन प्रमाणपत्र एगज. पी4 द्वारा समर्थित है।

(12) न्यायिक उदाहरणों के आधार पर अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि मृत कर्मचारी को मिलने वाले लाभ और भत्तों को उसके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी मासिक आय और एचआरए, सीसीए, मेडिकल के कारण काटी गई राशि की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। भत्ता, ईपीएफ, जीआईएस, एलआईसी, ऋण का पुनर्भुगतान आदि नहीं है। उसकी मासिक आय की ऐसी गणना में उसे बाहर रखा जाएगा। इस संबंध में ***श्रीमती हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क***

परिवहन निगम[2] का संदर्भ लिया जा सकता है; ***यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन***[3]; ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव और अन्य***[4]; ***श्यामवती शर्मा एवं अन्य बनाम करम सिंह एवं अन्य***[5] तथा ***रंजना प्रकाश बनाम मंडल प्रबंधक एवं अन्य***[6]***।*** ट्रिब्यूनल को मृतक की आय के आकलन के लिए मृतक के सकल वेतन से आयकर की वैधानिक कटौती करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव और अन्य***[7] में की गई टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है; ***श्यामवती शर्मा एवं अन्य बनाम करम सिंह एवं अन्य***[8] और ***रंजना प्रकाश बनाम मंडल प्रबंधक और अन्य***[9]। आकलन वर्ष 2017-18 के दौरान मृतक की कुल आय 4,21,668/- रुपये थी। आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों के अनुसार, 2,50,000/- रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं था। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1,50,000/- रुपये तक की छूट अनुमन्य थी। इस तरह की छूट के बाद रु. 22,000/- की कर योग्य आय पर 10% की दर से रु. 2,200/- का आयकर देय था, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 87 के मद्देनजर, रु. 5,000/- की छूट थी। कर योग्य आय रु. 5,00,000/- से कम होने की स्थिति में स्वीकार्य। इसलिए, कोई आयकर देय नहीं था और ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय से आयकर के लिए कोई कटौती नहीं करने में कोई त्रुटि नहीं की।

(13) मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 53 वर्ष होना अभिलेखीय साक्ष्यों से सिद्ध होता है। चूंकि, मृतक स्थायी सरकारी कर्मचारी था, इसलिए पैरा संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में ट्रिब्यूनल द्वारा 15% की वृद्धि करना आवश्यक था और यह उचित भी था ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी***

---

[2] 1998(4) आर.सी.आर.(सिविल) 177

[3] 2002(3) आर.सी.आर.(सिविल) 534 : 2002 (6) एससीसी 281

[4] 2008 (1) आरसीआर (सिविल) 359

[5] 2010 (3) आरसीआर (सिविल) 741(एससी)

[6] 2011 (4) आरसीआर (सिविल) 218

[7] 2008 (1) आरसीआर (सिविल) 359

[8] 2010 (3) आरसीआर (सिविल) 741(एससी)

[9] 2011 (4) आरसीआर (सिविल) 218

और अन्य[10] में इसके फैसले की धारा 61(iii)। इस प्रकार जोड़ने पर मृतक की मृत्यु के समय उसकी आय रु. 35,139 x 12 = 4,21,668 + (15%) 63,250 = रु. 4,84,918/- होती है।

(14) मृतक पर आश्रितों की संख्या दो (दावेदार विधवा और पुत्र) होने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती में अपने फैसले के पैरा संख्या 14 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। ***सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम***[11], मृतक की आय का 1/3 हिस्सा काटा जाना आवश्यक था और ट्रिब्यूनल द्वारा उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती करना उचित था। मृतक की आय का 1/3 हिस्सा उसके निजी खर्चों के लिए काटने पर दावेदारों की मृतक पर वार्षिक निर्भरता रु. 4,84,918/- घटाकर (1/3) रु. 1,61,639/- = रु. 3 हो जाती है। ,23,279/-

(15) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में अपने फैसले के पैरा संख्या 61 (vii) में कहा कि मृतक की उम्र गुणक लागू करने का आधार होनी चाहिए। सरला वर्मा के मामले (सुप्रा) में अपने फैसले के पैरा संख्या 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और मृतक की आयु 53 वर्ष होने के मद्देनजर, 11 का गुणक लागू था। हालाँकि, मृतक की उम्र 53 वर्ष थी और वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सात साल बाद सेवानिवृत्त हो जाता, लेकिन पुट्टम्मा और अन्य बनाम के.एल. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर। ***नारायण रेड्डी और अन्य***[12] में मृतक की आय को विभाजित करने के लिए 7 और 4 के विभाजित गुणक का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 7 वर्षों के लिए मूल्यांकन किया गया है और 4 वर्षों के लिए इसका आधा हिस्सा है और 11 के गुणक को उस समय मृतक की आय पर लागू किया जाना है। उनकी मृत्यु का मूल्यांकन किया गया। जब 11 के गुणक को मृतक पर दावेदारों की 3,23,279 रुपये की वार्षिक निर्भरता पर लागू किया जाता है, तो मृतक पर दावेदारों की निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजा 3,23,279 x 11 = 35,56,069/- रुपये आता है।

(16) प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में, 31.10.2017 को संदर्भ का उत्तर देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा संख्या 61 (viii) में पाया कि पारंपरिक प्रमुखों, अर्थात् संपत्ति की हानि, हानि पर उचित आंकड़े कंसोर्टियम और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः 15,000/- रुपये, 40,000/- रुपये और

---

[10] 2017 (4) आर.सी.आर. (सिविल) 1009

[11] 2009 (3) आर.सी.आर. (सिविल) 77

[12] 2014(1) आरसीआर (सिविल) 443

15,000/- रुपये होना चाहिए। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उपरोक्त राशि को हर तीन साल में 10% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। उस मामले में प्यार और स्नेह की हानि के लिए कोई अलग से राशि देय करने का आदेश नहीं दिया गया था। वर्तमान मामले में दुर्घटना 05.03.2017 को हुई और पारंपरिक मदों के तहत राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। ***मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरू राम और अन्य***[13] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी भाषा में 'कंसोर्टियम' एक अनिवार्य शब्द है जिसमें 'पति-पत्नी संघ', 'अभिभावक संघ' और 'फिलिअल कंसोर्टियम' शामिल हैं और मुआवजा दिया गया है। मृतक के पिता और बहन को पारिवारिक क्षति के लिए प्रत्येक को 40,000/- रु. हालाँकि, बेंच ने अपने फैसले के पैरा नंबर 8.7 में कहा कि कंसोर्टियम के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि 'लॉस ऑफ कंसोर्टियम' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी जैसा कि प्रणय सेठी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत उपर्युक्त पारंपरिक शीर्षों के अंतर्गत कुल राशि रु. 70,000/- देय है। उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल ने कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 40,000/- रुपये, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/- रुपये की राशि अपीलकर्ता दावेदारों को दी।

(17) यहां यह देखा जा सकता है कि मृतक की विधवा को देय पेंशन निर्भरता के नुकसान के लिए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे की राशि से कटौती योग्य नहीं है। इस संबंध में ***विमल कंवर और अन्य बनाम किशोर दान और अन्य***[14] और ***सेबेस्टियानी लाकड़ा और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य***[15]का संदर्भ दिया जा सकता है। इसी प्रकार, नियोक्ता द्वारा मृतक की विधवा को भुगतान की गई कोई भी अनुग्रह राशि उसके कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे से कटौती योग्य नहीं है। इस संबंध में ***नगर निगम एवं अन्य बनाम श्रीमती अजीत कौर और अन्य***[16] का संदर्भ लिया जा सकता है।.

(18) वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल ने हरियाणा 2006 के नियमों का हवाला देकर और शशि शर्मा के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए मुआवजे की राशि में

---

[13] 2018 (4) आर.सी.आर. (सिविल) 333

[14] 2013 (2) आरसीआर (सिविल) 945

[15] 2018 (4) आरसीआर (सिविल) 837

[16] 2008 (3) आरसीआर (सिविल) (पीएचएचसी) 29

से 26,67,168/- रुपये की कटौती की। 35,56,069/- रुपये का इस आधार पर कि अगले सात वर्षों के लिए अपीलकर्ताओं/दावेदारों मृतक-बलवान सिंह के आश्रितों को 31,752/- रुपये की दर से भत्ते के साथ वेतन देय होगा। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

> "23. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर। शशि शर्मा और अन्य (उपरोक्त) के अनुसार, मृतक बलवान सिंह के आश्रितों को निर्दिष्ट अवधि के लिए मृतक के वेतन की हानि के बराबर वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि मुआवजे की कुल राशि से कटौती योग्य है।
>
> 24. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, मृतक बलवान सिंह की उम्र 53 वर्ष थी। इसलिए, मृतक बलवान सिंह के परिवार के सदस्यों को 7 साल की अवधि के लिए वेतन और अन्य भत्ते की राशि पारिवारिक सहायता के रूप में मिलती रहेगी, जो मृतक बलवान सिंह ने अंतिम बार ली थी। वेतन विवरण एगज.पी4 के अनुसार, मृतक बलवान सिंह को वेतन के रूप में प्रति माह 35,139/- रुपये मिलते थे। हालाँकि, उनकी मृत्यु के बाद, मृतक बलवान सिंह के परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। अंतिम वेतन पर्ची एगज.पी4के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक को 3,207/- रुपये का एचआरए, 90/- रुपये का साइकिल भत्ता और 90/- रुपये का धुलाई भत्ता मिल रहा था, जो 3,387/- रुपये होता है और यह मृतक बलवान सिंह के आश्रित को राशि देय नहीं है। इसलिए, सरकार द्वारा मृतक के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के रूप में कुल वित्तीय सहायता रु. 31,750/- (35139 – 3387) प्रति माह या रु. 3,81,024/- प्रति वर्ष (31752 x) होती है। 12), जिसका भुगतान मृतक बलवान सिंह के आश्रितों को अगले सात वर्षों तक किया जाएगा। इसलिए, कुल राशि रु. 26,67,168/- (381024 x 7) होती है। तदनुसार, निर्भरता के नुकसान के कारण दावेदार 8,88,901/- (3556069 – 2667168) रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।

(19) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील के मद्देनजर कि मृतक के आश्रितों को ऐसा कोई वेतन और भत्ता देय नहीं था और उन्हें केवल नियमों के तहत अनुमेय पेंशन का भुगतान किया गया था और पैरा संख्या 24 में की गई टिप्पणियां निर्णय गलत थे, तथ्यात्मक कथनों की सत्यता पर प्रतिवादी संख्या 2-बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया था, दिनांक 28.08.2020 के आदेश के तहत पैरा संख्या 24 में की गई टिप्पणियों के संबंध में ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी के स्पष्टीकरण को बुलाया गया था। निर्णय का और वह सामग्री भी जिसके आधार पर इसे बनाया गया था।

(20) आदेश दिनांक 28.08.2020 के अनुपालन में ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 14.09.2020 प्रस्तुत किया है और उसी का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "मुझे कांता देवी और अन्य बनाम एमएसीटी मामले में इसे प्रस्तुत करने का सम्मान मिला है। राणा कुमार और अन्य ने 31.10.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णय लिया, "रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम" शीर्षक वाले केस कानून पर भरोसा करते हुए कटौती की गई थी। शशि शर्मा और अन्य IV(2016) ACC 340 (SC)" और हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या G.S.R.19/Cons./Art/309/2006 दिनांक 01.08.2006 और वित्तीय सहायता के लिए मानदंड का उल्लेख किया गया है अंतर्गत:-
>
> 5.(1) किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में उस वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि मिलती रहेगी जो मृतक कर्मचारी द्वारा अंतिम बार सामान्य अवधि में बिना किसी विशिष्ट राशि के प्राप्त की गई थी। दावा करना।
>
> (ए) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय उसने पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी;
>
> (बी) उस तारीख तक बारह वर्ष की अवधि के लिए जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, जो भी कम हो, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता, यदि उसकी मृत्यु के समय कर्मचारी पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता, लेकिन अड़तालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई थी।
>
> यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अंतिम वेतन पर्ची एगज. पी1 के अनुसार, मृतक को वेतन के रूप में प्रति माह 35,139/- रुपये की राशि मिल रही थी, जिसमें से 3,207/- रुपये एचआरए, 90/- रुपये साइकिल भत्ता और 90 रुपये थे। /- धुलाई भत्ते में कुल 3,387/- रुपये की कटौती की गई और मृतक के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के रूप में कुल वित्तीय सहायता 31,752/- रुपये बनती है, जिसका भुगतान मृतक बलवान सिंह के आश्रितों को किया जाएगा। अगले सात साल.
>
> आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि बहस के समय किसी भी पक्ष द्वारा कोई अन्य मामला कानून या नियम प्रस्तुत नहीं किया गया/अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में नहीं लाया गया।''

(21) हरियाणा 2006 के नियम 5(1) के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर मृत कर्मचारी का परिवार वित्तीय सहायता के रूप में मृतक कर्मचारी द्वारा अंतिम बार लिए गए वेतन और अन्य भत्तों के बराबर

राशि प्राप्त करना जारी रखने का हकदार है। यदि मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय पैंतीस वर्ष की आयु नहीं हुई हो तो सामान्य तौर पर पंद्रह वर्षों तक कोई विशिष्ट दावा किए बिना; बारह वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था, लेकिन अड़तालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाया था और सात वर्ष के लिए वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी कम हो, यदि मृत कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के समय अड़तालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। हरियाणा 2006 नियमों के नियम 5(2) के तहत परिवार सामान्य नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा जब उस अवधि के दौरान परिवार को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही हो। शशि शर्मा के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हरियाणा 2006 नियमों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि, मृतक सरकारी कर्मचारियों द्वारा अंतिम बार लिए गए वेतन और अन्य भत्तों के बराबर होगी, जिसे बाहर रखा जाएगा। एम.वी. के तहत उन्हें देय मुआवजे से अधिनियम, 1988.

(22) हालाँकि, वर्तमान मामले में, मृतक-बलवान सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में खलासी के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ने हरियाणा 2006 नियमों के समान कोई नियम नहीं बनाया है, जो मृत कर्मचारी के अंतिम वेतन और भत्ते के बराबर राशि के भुगतान द्वारा अपने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे किसी भी नियम के अभाव में अपीलकर्ता/दावेदार मृतक द्वारा अंतिम बार लिए गए सात साल या किसी अन्य अवधि के वेतन और अन्य भत्तों के बराबर राशि के भुगतान द्वारा किसी भी अनुकंपा वित्तीय सहायता के हकदार नहीं थे। पीडब्लू-3 चंदर भान, बैलदार, एक्सईएन कार्यालय, दिल्ली ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि दावेदार नंबर 1-मृतक-बलवान सिंह की विधवा को विभाग से पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रति माह 13,660/- रुपये की राशि मिल रही थी। अपीलकर्ता/दावेदार नंबर 1 मृत कर्मचारी बलवान सिंह की विधवा को पेंशन का भुगतान भी विरोधाभासी है और इस प्रकार अपीलकर्ताओं/दावेदारों की भुगतान की पात्रता के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा अपीलकर्ताओं/दावेदारों को ऐसी किसी भी अनुकंपा वित्तीय सहायता के वास्तविक भुगतान दोनों को अस्वीकृत करता है। मुआवजे की राशि में से अनुकंपा वित्तीय सहायता की राशि की कटौती के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं थीं। ट्रिब्यूनल द्वारा अपने निर्णय/निर्णय के पैरा संख्या 24 और 25 में की गई टिप्पणियाँ गलत थीं। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों को देय 35,56,069/- रुपये की मुआवजा राशि में से 26,67,168/- रुपये की राशि गलत तरीके से काट ली और विवादित पुरस्कार भौतिक अवैधता से ग्रस्त है और इसमें संशोधन के योग्य है।

(23) जाहिर तौर पर, विवादित पुरस्कार के पैरा संख्या 24 और 25 में टिप्पणियाँ ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्यों की गलत धारणा पर की गई थीं कि मृतक, जो हरियाणा का निवासी था, हरियाणा सरकार का कर्मचारी था। हमारी कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों की ग़लती को स्वीकार करती है और इसके मद्देनजर अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। (***के.पी. तिवारी बनाम म.प्र. राज्य***[17] देखें)। गलती करना मानवीय है और कोई भी अचूक नहीं है। ऐसा न्यायाधीश अभी तक पैदा नहीं हुआ है जिसने कोई गलती न की हो। (***अमर पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी***[18] ***(एससी)*** और ***"के" एक न्यायिक अधिकारी***[19] के मामले में देखें)। वास्तविक त्रुटि के लिए किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कदाचार, बाहरी प्रभाव, किसी भी प्रकार की संतुष्टि आदि के स्पष्ट आरोप न हों, अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इस आधार पर शुरू नहीं की जानी चाहिए कि न्यायिक अधिकारी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है। (***काशी नाथ रॉय बनाम बिहार राज्य***[20] और ***कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य***[21] देखें)। उच्च न्यायालयों की भूमिका अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह होती है और वरिष्ठ न्यायालयों का दृष्टिकोण सुधारात्मक होना चाहिए। (देखें "***के" के मामले में एक न्यायिक अधिकारी***[22])। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कोई शिकायत या कोई अन्य सामग्री नहीं है कि निष्कर्ष किसी दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों से प्रेरित थे ताकि प्रशासनिक पक्ष पर ट्रिब्यूनल के विद्वान पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता हो।

(24) वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने याचिका दायर करने की तारीख से पूरी राशि की वसूली तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। ***अबाती बेजबरुआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य***[23]में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग ब्याज दर

---

[17] 1994 सप्प. (1) एससीसी 540

[18] 2012 (3) आर.सी.आर.(सिविल) 963

[19] (2001) 3 एससीसी 54

[20] 1996(2) आरसीआर (सीआरएल.) 340

[21] 2019(10) एससीसी 640

[22] (2001) 3 एससीसी 54

[23] (2003) 3 एससीसी 148

दी जा रही है और माना गया कि ब्याज की दर उचित होनी चाहिए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में बदलाव, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाई जाने वाली नीति, मामला कितने समय से लंबित है, हानि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। जीवन का आनंद आदि। पुट्टम्मा के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय का पालन किया गया था। उपर्युक्त न्यायिक उदाहरणों में टिप्पणियों के मद्देनजर, मुद्रास्फीति की दर, अर्थव्यवस्था में बदलाव, आरबीआई की ऋण ब्याज दर, सावधि जमा रसीदों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुमत ब्याज दर और अन्य प्रासंगिक कारकों, भुगतान के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देश 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज को अनुचित/अवैध नहीं कहा जा सकता।

(25) उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दावेदार याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से लागत और ब्याज के साथ 36,26,069/- रुपये के मुआवजे के भुगतान के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा दावेदारों को दी गई 9,58,901/- रुपये की राशि उपरोक्त राशि से कटौती के लिए उत्तरदायी होगी। 26,67,168/- रुपये की बढ़ी हुई राशि में से, 20,67,168/- रुपये की राशि दावेदार नंबर 1-विधवा को देय होगी और 6,00,000/- रुपये की राशि दावेदार नंबर 2 मृतक का पुत्र प्रतिवादी नंबर 2को देय होगी। बीमा कंपनी को उपरोक्त राशि का भुगतान अपीलकर्ताओं/दावेदारों के खातों में जमा करके करने का निर्देश दिया जाता है (जिसका विवरण अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान वकील द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील को प्रस्तुत किया जाएगा) -बीमा कंपनी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर) आरटीजीएस या किसी अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से अपीलकर्ताओं/दावेदारों के खातों का विवरण प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर। ऐसे क्रेडिट पर, अपीलकर्ता/दावेदार अपने संबंधित खातों में जमा की गई राशि को निकालने के हकदार होंगे।

(26) तदनुसार दिनांक 31.10.2018 के निर्णय के उपरोक्त संशोधनों के संदर्भ में लागत के साथ अपील की अनुमति दी जाती है।

(27) हालाँकि, इस अपील से अलग होने से पहले यह देखा जा सकता है कि कभी-कभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा तथ्य या कानून में त्रुटियों वाले गलत आदेश पारित किए जाते हैं। अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए इसके खिलाफ अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं करने की स्थिति में ऐसे आदेशों के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर हानि हो सकती है। यह उचित होगा कि न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने और अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा बार-बार की जाने वाली त्रुटियों से बचने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जाए। चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ को समय-समय पर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार विजिलेंस या रजिस्ट्रार न्यायिक और संबंधित

जिला और सत्र न्यायाधीशों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करके न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित ऐसे गलत आदेशों से जुड़े मामलों को संकलित करने और न्यायिक अधिकारियों को की गई त्रुटियों को इंगित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने उनके लिए आयोजित इंडक्शन/रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान संबंधित न्यायिक अधिकारियों और इसमें शामिल मामलों के विवरण का खुलासा न करने के समर्पित प्रयास किए, हालांकि निर्णयों की रिपोर्टिंग के मद्देनजर इसके बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। इस न्यायालय के आदेशों को इस न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड करना।

(28) इस आदेश की एक प्रति निदेशक (प्रशासन), चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ को अपेक्षित अनुपालन के लिए और संबंधित न्यायिक अधिकारी को सूचना और मार्गदर्शन के लिए भेजी जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी